जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 20 संख्याः 96 प्रभात जालोर, रविवार 13 जुलाई, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

फ्रेंच ओपन फाइनल के ठीक पांच सप्ताह बाद, विंबलडन फाइनल में सिनर और अल्कराज़ एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अल्कराज़ ने फ्रेंच ओपन का फाइनल पांच घंटे 29 मिनट में जीता था और रविवार को इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। अल्कराज़ का ग्रैण्डस्लैम फाइनल में 5-0 का रिकॉर्ड है। सिनर के नाम पर तीन ग्रैण्डस्लैम खिताब हैं। अल्कराज़ विंबलडन में लगातार 24 मैच जीत चुके हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अभी तक जो 12 मैच खेले गए हैं, उनमें से अल्कराज़ ने आठ और सिनर ने चार मैच जीते हैं। अल्कराज़ ने इटली के खिलाड़ी के खिलाफ पिछले पांचों मुकाबले जीते हैं। अल्कराज़ ने सेमीफाइनल में टेलर फ्रिट्ज़ को 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 (6) से हराकर लगातार तीसरी विंबलडन चैंपियनशिप जीतने की तरफ मजबूत कदम बढ़ ाए थे। यानिक सिनर ने सेमीफाइनल मुकाबले में नोवाक जोकोविच को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में सिनर ने जोकोविच को 6-3, 6-3, 6-4 से हरा दिया। खिताबी मैच में अब उनका सामना कार्लोस अल्कराज़ से होगा।

भागवत, मोदी से छः दिन पहले 75 वर्ष के हो जायेंगे....(1)

क्या उस दिन अपने पद से इस्तीफा देकर, प्र.मंत्री के लिए इस्तीफे का मार्ग प्रशस्त करेंगे?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 जुलाई। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 75 वर्ष की आयु में इस्तीफा देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? ज्ञातव्य है कि यह आयु-सीमा खुद मोदी ने ही 2014 में प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद निर्धारित की थी, ताकि भाजपा में वे सर्वोच्च बने रहें और कोई वरिष्ठ नेता उनके निर्णयों को न चुनौती दे सके, न उलट सके।

हाल ही में नागपुर में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भागवत द्वारा किये गये 75 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के आव्हान को मीडिया ने मोदी के लिए संकेत के रूप में देखा। हो सकता है कि भागवत ने व्यापक रूप से मोदी की ओर इशारा किया हो, लेकिन असल में वे स्वयं के संदर्भ में बात कर रहे थे। भागवत 11 सितंबर को, मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) से छह दिन पहले, 75 वर्ष के हो जायेंगे।

आरएसएस में नेतृत्व परिवर्तन की कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि संघ का संविधान इसकी पूरी व्यवस्था करता है। वर्तमान में संघ के सरकार्यवाह (महासचिव) दत्तात्रेय होसबोले, जो अंग्रेज़ी साहित्य में स्नातकोत्तर हैं, को भागवत के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है। वे मार्च 2021 में सुरेश "भैयाजी" जोशी की जगह सरकार्यवाह बने थे, जो इस संगठन का दूसरा सबसे ऊँचा पद है। अगर 75 की उम्र की सीमा लागू होती है, तो होसबोले दिसंबर 2029 तक संघ के प्रमुख रह सकते हैं।

- हाल ही में भागवत ने नागपुर में "बुक रिलीज़" आयोजन पर सार्वजनिक रूप से कहा था, कि 75 की आयु पहुंचते ही भाजपा/आर.एस.एस. के नेता को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। भागवत उस समय अपने इस्तीफे की बात कर रहे थे, न कि मोदी के।
- भागवत के इस्तीफा देने से संघ की गतिविधियों में कोई व्यवधान नहीं पड़ता, क्योंकि संघ के संचालक का उत्तराधिकारी नियुक्त करने की बड़ी स्थापित व्यवस्था है। अगर मोहन भागवत रिटायर होते हैं, तो सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ऑटोमैटिकली संघ प्रमुख बन जाते हैं।
- ऐसा कहा जाता है कि मोदी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था, उस समय उन्होंने यह सिद्धांत स्थापित करवाया था, कि, जिन नेताओं की आयु 75 वर्ष हो जायेगी, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। शायद इस सिद्धांत का व्यवहारिक महत्व यह था, कि मोदी से सीनियर कोई नेता भाजपा में न बचे, जो उनकी आंख में आंख डालकर बात कर सके।
- अब यह सिद्धांत ही भाजपा के गले की घण्टी बन गया है। मोदी को विदाई देने की स्थिति में नहीं है भाजपा, और न ही कोई उन्हें यह सुझाव दे सकता है। अतः स्वयं अपना इस्तीफा देकर, भागवत, मोदी पर इस्तीफे का दबाव बनाना चाह रहे हैं?

तथापि, मोदी ने अब 75 वर्ष की सेवानिवृत्ति सीमा की चर्चा बंद कर दी है, जिसे उन्होंने 2014 में सत्ता में आते ही स्थापित किया था। इसका कारण यह है कि उन्हें पार्टी के शीर्ष स्तर से कोई चुनौती नहीं दिखती, न ही उन्हें हटाने की कोई सक्रिय कोशिश पार्टी के अन्दर ही दिखाई दे रही है। सच तो यह है कि मोदी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पिछले दस दिन में पटना के तीन प्रमुख व्यक्तियों की हत्या

तेजस्वी यादव ने एक्स पर सवाल उठाया, कि अचेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी में बिगढ़ती हुई कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 जुलाई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने पिछले 10 दिनों में हुई हत्याओं तथा शुक्रवार शाम पटना के रामकृष्णा नगर में एक स्थानीय व्यापारी की गोली मारकर की गई हत्या के बाद यह बात कही।

एक्स पर एक पोस्ट में यादव ने लिखा, "पटना में व्यापारी विक्रम झा की गोली मारकर हत्या! डीके टैक्स ट्रांसफर इंडस्ट्री राज्य में अराजकता की स्थिति का मुख्य कारण है।" उन्होंने मुख्यमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए आगे लिखा, "बेहोश मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? रोज़ हो रही सैकड़ों हत्याओं के लिये जिम्मेदार कौन है? भ्रष्ट "भूंजा पार्टी" को जवाब देना होगा।"

पटना पूर्व के एसपी परिचय कुमार ने कहा "पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हत्या के पीछे की सही वजह अभी पता नहीं चल पाई है। जांच चल रही है।" उन्होंने यह भी बताया कि झा के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और आरोपी की पहचान करके उसे पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है।

- चार जुलाई को पहली हत्या गोपाल खेमका की हुई। फिर 10 जुलाई को माइनिंग से जुड़े 50 वर्षीय बिजनसमैन की हत्या उनके रानीतलाव में स्थित निवास के बाहर हुई। तथा शुक्रवार को पटना की संभ्रांत कॉलोनी रामकृष्ण नगर में, स्थानीय व्यापारी विक्रम की हत्या हुई। पर इन सभी हत्याओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत विचलित करती है।
- तेजस्वी यादव की आक्रामक टिप्पणी के उत्तर में एन.डी.ए. नेताओं ने जवाब में कहा, "विपक्ष (आर.जे.डी.) पुनः अपना जंगलराज स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, और ये हत्याएं इस प्रयास का ही नतीज़ा हैं।"

इस हत्या से ठीक पहले, 10 जुलाई को रानीतालाब में एक 50 वर्षीय बजरी-खनन व्यवसायी की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

निशक्त हुए एईएन के बकाया वेतन का ब्याज सहित भुगतान करें

जयपुर, 12 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने एईएन के पद पर कार्यरत प्रार्थी के ब्रेन हेमरेज के कारण 80 फीसदी निशक्त हो जाने और इस कारण विभाग में गैर हाजिर रहने पर उसे वेतन नहीं देने को गलत माना है। इसके साथ ही, संबंधित विभाग को निर्देश दिया है कि वह प्रार्थी को चार सप्ताह में 6 फीसदी ब्याज सहित उसके बकाया वेतन व अन्य सेवा परिलाभ का भुगतान करे। वहीं, प्रार्थी को हर्जाना राशि के तौर पर 25 हजार रुपए भी दिए जाएं। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल ने यह आदेश सुनील कुमार गुप्ता की याचिका पर दिया।

- हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को इस संबंध में पब्लिक सरक्युलर जारी करने के भी निर्देश दिये।

अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे इस संबंध में पब्लिक सर्कुलर जारी करें, ताकि निशक्त व्यक्तियों को निशक्त अधिनियम 2016 का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। मामले से जुड़े अधिवक्ता सीपी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लालू यादव के ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप अपनी अलग पार्टी बनायेंगे?

यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में तेज प्रताप ने अपने पुराने क्षेत्र महुआ में एक रोड शो किया, जिसमें नया हरा व सफेद झण्डा लहराया गया, जिस पर बड़े-बड़े शब्दों में लिखा था, "टीम तेज प्रताप यादव"

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 12 जुलाई। क्या राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव, जिन्हें पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है, अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं?

इस सवाल को लेकर अटकलें उस समय तेज हो गईं, जब तेज प्रताप ने अपने पुराने राजनीतिक गढ़ महुआ में एक रोड शो आयोजित किया, जिसमें वो "टीम तेज प्रताप यादव" लिखे हुए हरे और सफेद झंडे लहराते नजर आए।

राजद परिवार में, इस बात को लेकर लंबे समय से संघर्ष चल रहा है कि पार्टी के संस्थापक की राजनीति और विरासत का असली हकदार कौन है? जहां लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने खुद को पार्टी और लालू की राजनीतिक विरासत के असली उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित कर लिया है, वहीं तेज प्रताप अक्सर असहज और विद्रोही रुख में दिखाई देते रहे हैं। लालू की बेटियां, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, भी समय-समय पर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जताती रही हैं।

- लालू के परिवार में तेज प्रताप के अलावा, पुत्री मीशा भारती व रोहीनी आचार्य भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रखती हैं और दर्शाती हैं, समय समय पर।
- पारिवारिक परिस्थितियों से परिचित लोगों का मानना है कि तेज प्रताप उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी को स्वीकार कर चुके हैं, पर वे टिकट के बंटवारे में तथा पार्टी के अन्य राजनीतिक मामलों में पूर्ण रूप से बैक सीट पर ही बैठे रहने को तैयार नहीं हैं, समय समय पर, और महत्व पाने की इच्छा दिखा चुके हैं।
- अंततोगत्वा तेज प्रताप को पार्टी का टिकट देकर चुनाव लड़वा दिया जायेगा और वे संतुष्ट होकर बैठ जायेंगे।
- पर, फिलहाल उन्होंने महुआ में अपने भाषण में जोर शोर से कहा, "मैं जनता की इच्छा के अनुसार ही काम करता हूँ। मैं, वहीं से चुनाव लड़ूँगा, जहां से जनता चाहती है, और मेरी पार्टी का क्या होगा, यह तो समय ही बतायेगा।"

तेज प्रताप के पास पार्टी संगठन का कोई बड़ा आधार नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ वफादार समर्थकों का समूह जरूर है। इसके साथ ही, उन्हें पार्टी से निष्कासित किए जाने को लेकर सहानुभूति भी मिल रही है। कई लोग उनके साथ किए गए इस व्यवहार को "अत्यधिक कठोर" मानते हैं। तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए उस समय निष्कासित किया गया, जब उन्होंने फेसबुक पोस्ट में खुद को अनुष्का यादव नाम की महिला के साथ रिश्ते में बताया था। बाद में वह पोस्ट हटा दी गई, लेकिन पार्टी ने इसे "गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार" बताते हुए निष्कासन की कार्रवाई की।

सामाजिक न्याय के प्रति अपनी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्व न्यायालयों में लम्बित केसों के निस्तारण के लिये एनओसी बनायें

जयपुर, 12 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजस्व व अपीलीय राजस्व न्यायालयों में पिछले कई दशकों से लंबित चल रहे केसों को गंभीरता से लेते हुए, राज्य सरकार से कहा है कि वह इनका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करे और अपेक्षा है कि वह इन न्यायालयों में लंबित मुकदमों के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करेगी। अदालत ने कहा कि पुराने मामलों को प्राथमिकता न दिए जाने के

- हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राजस्व व अपीलीय न्यायालयों में अफसरों की नियुक्ति के लिये व्यापक परीक्षा आयोजित करने के लिये कहा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'बिहार में 10 प्रतिशत वोटर लिस्ट, यानी 77 लाख मतदाता फर्जी हैं'

स्वराज्य मैगज़ीन द्वारा किये अध्ययन व डेमोग्राफिक (जनसांख्यिकीय) सर्वे के अनुसार प्रदेश की वर्तमान मतदाता सूची में 7.89 करोड़ वोटर दिखाये गये हैं, पर मैगज़ीन के डेमोग्राफिक सर्वे के अनुसार असल में मतदाताओं की सही संख्या 7.12 करोड़ ही है

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 12 जुलाई। जनसांख्यिकीय पुनर्निर्माण (डैमोग्राफिक रीकन्स्ट्रक्शन) पर आधारित एक नई रिसर्च में सामने आया है कि बिहार की वोटर लिस्ट में लगभग 10 प्रतिशत नाम अवैध हो सकते हैं। ये वो नाम हैं, जिन्हें जन्म, मृत्यु या प्रवासन (माइग्रेशन) जैसे किसी भी जनसांख्यिकीय कारण से समझाया नहीं जा सकता, फिर भी वो वोटर लिस्ट में बने हुए हैं, चुनावी प्रक्रिया को विकृत करते हुए और लोकतंत्र को कमजोर करते हुए।

- इसका मतलब है, प्रत्येक सीट पर औसतन 30 हजार फर्जी वोटर हैं। अतः कांटे की टक्कर वाले चुनाव में जहां हार-जीत का फैसला सदा बहुत कम वोटों से होता है, ये फर्जी वोट बहुत भारी महत्व रखते हैं।
- उदाहरण के लिए, 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में 20 प्रतिशत सीटों पर हार जीत केवल 2.5 प्रतिशत वोटों के अन्तर से हुई थी। तथा 17 सीटें तो ऐसी थीं, जहां हार-जीत केवल एक प्रतिशत वोट से हुई थी।
- ये फर्जी वोट, जिनकी संख्या लगभग 30 हज़ार है, हर सीट पर कहां से आये, ये लोग कौन हैं, इसको कोई नहीं समझा पा रहा है। मृत्यु, जन्म या पलायन की डेमोग्राफिक स्टडी का भी सहारा लेकर कोई नहीं समझा सकता।
- यह तो ऐसा है जैसे पूरा पुणे शहर, दुनिया से गायब हो जाये, परन्तु वहां के बाशिन्दे हर चुनाव में आकर अपना वोट डाल जाते हैं।

कल्पना कीजिए कि भारत के नक्शे से एक पूरा शहर, मान लीजिए, पुणे, अचानक गायब हो जाए, लेकिन उसके निवासी हर चुनाव में वोट डालते रहें। यह कोई विचार प्रयोग नहीं है, बल्कि बिहार की चुनावी सच्चाई है।

स्वराज्य पत्रिका ने अपने अध्ययन, "डैमोग्राफिक रीकन्स्ट्रक्शन एण्ड इलैक्टोरल रोल इन्फ्लेशन : एस्टिमेटिंग द लेजिटिमेट वोटर बेस इन बिहार, इण्डिया (2025)" में पूरी तरह आधिकारिक आँकड़ों पर आधारित कठोर जनसांख्यिकीय गणनाओं का उपयोग किया है। इसमें शामिल हैं: पुराने चुनावी रिकॉर्ड, उम्र के अनुसार जीवित रहने की संभावना, जन्म दर के अनुमान और राज्य के भीतर/बाहर प्रवासन के आँकड़े।

परिणाम चौंकाने वाला है: बिहार की मौजूदा वोटर लिस्ट में 77 लाख

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में संसाधन व सुविधायें क्यों नहीं हैं'

जयपुर, 12 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने, अदालती आदेशों के बाद भी, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में संसाधन व सुविधाएं नहीं होने को गंभीर माना है। वहीं, आगामी सुनवाई 18 जुलाई को मुख्य सचिव को व्यक्तिगत तौर पर शपथ पत्र व तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित पेश होकर यह बताने के लिए कहा है कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई की है।

- हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा कि शपथ पत्र व तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ पेश होकर बतायें कि अभी तक क्या कार्यवाही की है।

अदालत ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए उचित संसाधन व

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)